

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस
राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./138/2012/बाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोंडेंटगण

1. नैनसिंह पुत्र रणजीतिसिंह वगै. बनाम 1.राजा का मु. ईश्वरसिंह

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थिति

1. वकील श्री दामोदर कुमार चौधरी अपीलान्त की ओर से।
2. वकील श्री अम्बालाल जोशी, श्री कुमार कौशल जोशी रेस्पोंडेंट संख्या 1/1 से 4/3 व 3/1 से 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक:- 04.12.2019

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांत ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। तामिल फर्जी तरीके से कराया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर अपीलांत की सम्यक तामिल नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय में बंटवाड़ा सहमति से बताया गया है जबकि अपीलांत द्वारा किसी प्रकार की सहमति नहीं दी गई थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.01.2012 को लंगेरा गांव में भूमि का बंटवाड़ा करवाने के लिये पदमसिंह पुत्र राजदानसिंह हल्का पटवारी व आर आई को लेकर हमारे कब्जासुद व ढाणी वाली भूमि पर आया और हल्का पटवारी के मार्फत हम अपीलार्थीगण को यह बताया कि यह भूमि हमारे खाते की है। अपीलार्थीगण दिनांक 11.01.2012 को बाड़मेर आये व सारी जानकारी प्राप्त की एवं नकले मांगी जो दिनांक 17.01.2012 को प्राप्त हुई। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले प्राप्त हुई तब सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील तकनीकी बिंदु पर खारिज नहीं करके गुणावगुण पर किया जावे जिस से अपीलांत के मेरा हित प्रभावित होता है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।



वकील रेस्पोंडेंट संख्या 1/1 से 4/3 व 3/1 से 6 ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांत के नाम जारी सम्मन पर तामिल पर्याप्त हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 25.09.1991 की आदेशिका में बावजूद तामिल अपीलांत अनुपस्थित। अपीलांत को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होने के बावजूद 18 वर्ष बाद अपील पेश की गई जिसका कारण मामले को लंबा करने हेतु पेश किया गया। वादग्रस्त आराजी को लेकर अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 14/2002 में शंकरसिंह द्वारा दावा पेश किया इसमें अपीलांत पक्षकार रूप में संयोजित किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांतगण ने चैनसिंह सोढा को वकील नियुक्त किया गया। अपीलांतगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना-पत्र में नहीं किया गया है। अपीलांतगण ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक-एक दिन का विवरण बताना होता है जबकि अपीलांत द्वारा सुदीर्घ अवधि के बाद पेश अपील में हुई देरी का विवरण नहीं बताया गया। अपीलांत की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

RRT 2018-19(Supp.) Page 72

RLW 2013(2) Page 1096

RRT 2011(2) Page 786

RRT 2016-17(Supp.) Page 631

RRT 2017(1) Page 117



अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांतगण के नाम जारी सम्मन की फर्द पर तामिल की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलांत के सम्मन स्वयं से तामिल संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद तामिल उपस्थित नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.1991 को अपीलांत के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी को लेकर एक राजस्व वाद संख्या 14/2002 पेश हुआ जिसमें अपीलांतगण ने अधिवक्ता चैनसिंह सोढा को वकील नियुक्त किया गया फिर भी अपीलांत को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी कैसे नहीं इसको अपीलांतगण द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया। अपीलांत द्वारा की गई देरी सदभाविक

राजस्व अपील प्राधिकारी
- बाड़मेर

नहीं है। अपीलांटगण येन-केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं: और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलांट द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 18 वर्ष 03 माह की देरी के बाद पेश की गई जबकि इतनी सुदीर्घ अवधि को Explain भी नहीं किया गया। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते हैं।

अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 96/1991 बअनवान राजा बनाम रूगसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.1993 को यथावत रखा जाता है।



यह आदेश आज दिनांक 04.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक
04/12/19
(नाथूसिंह रस्तोगी) अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांक
04/12/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

